Coastal Regulation Zone (Hindi)

भारत में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) एक नियामक ढांचा है जो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए समुद्र तट के पास मानव और औद्योगिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है।

भारत में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) पहली बार 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था।

इसे शुरुआत में 1991 में अधिसूचित किया गया था, फिर 2011 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया गया और तब से इसमें कई बार छोटे संशोधन किए गये हैं।

हाल ही में, शैलेश नायक समिति की सिफारिशों के आधार पर 2018-2019 में इसमें संशोधन किया गया है।

भारत में सीआरजेड के वर्तमान प्रकार में निम्नलिखित शामिल हैं:

Types of Coastal Regulation Zones:

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

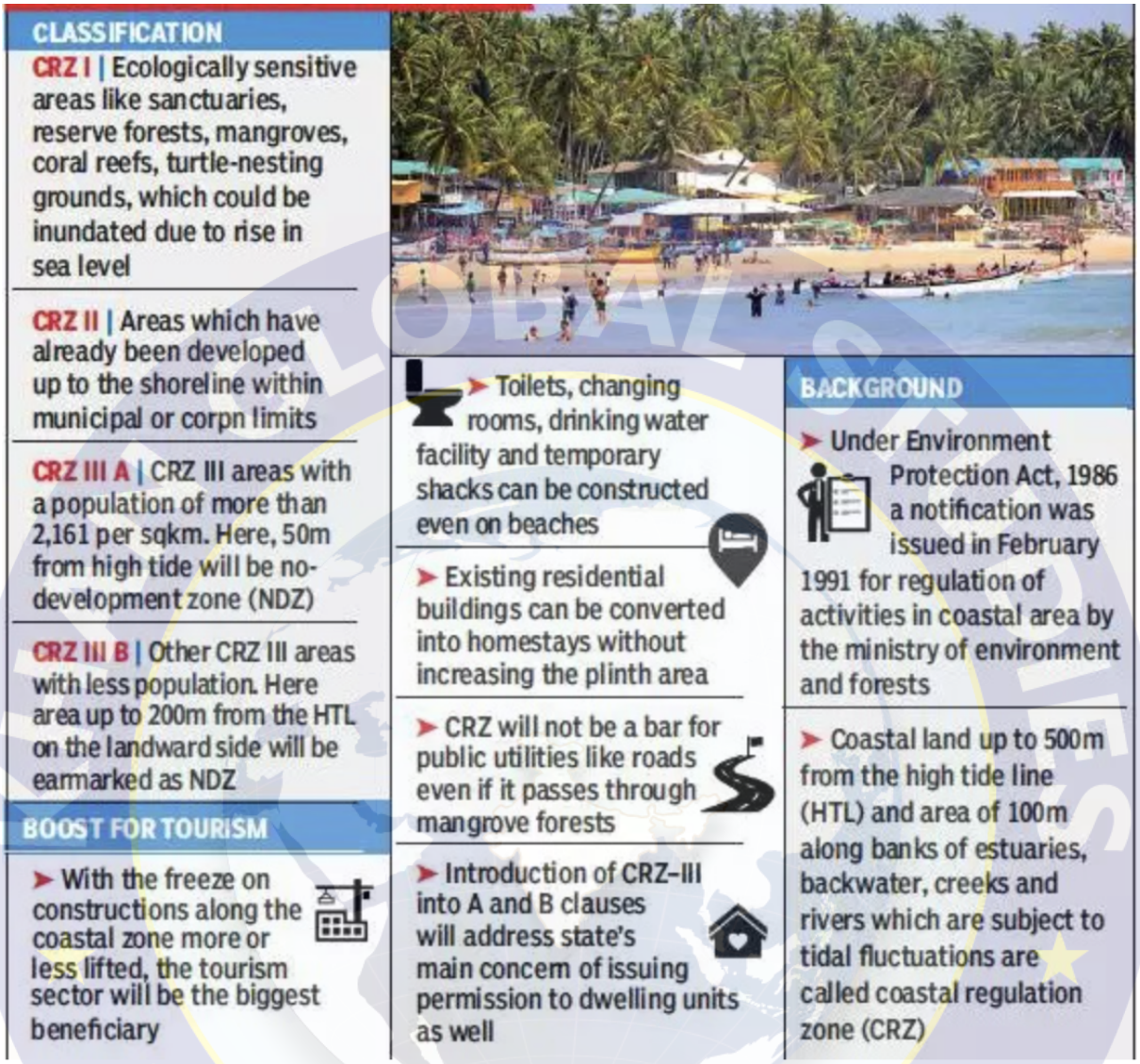

सीआरजेड श्रेणी	विवरण	स्वीकार्य गतिविधियाँ	प्रतिबंध
सीआरजेड-I	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र जैसे मैंग्रोव, मूंगा चट्टानें और अंतर्ज्वारीय क्षेत्र। आगे सीआरजेड-1A और सीआरजेड-1B में विभाजित किया गया है।	सीआरजेड-1A: मैंग्रोव वॉक, ट्री हट्स, नेचर ट्रेल्स जैसी इको-टूरिज्म गतिविधियां। सीआरजेड-1B: बंदरगाहों, समुद्री संपर्कों के लिए भूमि पुनर्ग्रहण।	रणनीतिक और सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं के लिए कुछ अपवादों के साथ, विकास पर कड़े प्रतिबंध।
सीआरजेड-II	वे क्षेत्र जो पहले से ही तटरेखा तक या उसके निकट काफी हद तक विकसित हो चुके हैं। शहरी क्षेत्र शामिल हैं।	फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) में वृद्धि, रिसॉर्ट्स का निर्माण और अन्य पर्यटन सुविधाएं।	शहरी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ निर्माण की अनुमति दी गई है।
सीआरजेड-III	सीआरजेड-I या II के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को	घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हाई टाइड लाइन (HTL) से नो डेवलपमेंट ज़ोन	एनडीजेड में कम आबादी वाले क्षेत्रों में सख्त

	छोड़कर अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्र। इसमें ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्र शामिल हैं।	(NDZ) को 200 मीटर से घटाकर 50 मीटर कर दिया गया, जिससे तट के करीब निर्माण की अनुमति मिल गई। सीआरजेड-III ए (घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्र) में उच्च ज्वार स्तर से 50 मीटर का कोई विकास क्षेत्र नहीं है, जबकि सीआरजेड-III बी (कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्र) में 200 मीटर का कोई विकास क्षेत्र नहीं है।	मानदंडों के साथ होटल, रिसॉर्ट के निर्माण की अनुमति नहीं है।
सीआरजेड-IV	तट से 12 समुद्री मील दूर तक तटीय जल क्षेत्र और ज्वारीय प्रभावित जल निकायों का जल क्षेत्र।	भूमि पुनर्ग्रहण, बंदरगाहों, बंदरगाहों और सड़कों की स्थापना के लिए अनुमति; उपचारित अपशिष्टों का निर्वहन; और स्मारकों या स्मारकों का निर्माण।	अपतटीय गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर, हालांकि पहले की तुलना में कम कठोर।

सीआरजेड अधिसूचना 2011 की तुलना में प्रमुख परिवर्तन

- नवीनतम नियमों का उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, तटीय पर्यावरण का संरक्षण करना और पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना है।
- नियम पूर्व सीआरजेड मंजूरी के बिना शुरू की गई परियोजनाओं के लिए कार्योत्तर मंजूरी की अनुमति देते हैं, मंजूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करते हैं और पर्यटन बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हैं।

फ़ीचर	सीआरजेड 2011 अधिसूचना	सीआरजेड 2018 अधिसूचना
सीआरजेड-I	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र, जिनमें मैंग्रोव, मूंगा चट्टानें और रेत के टीले शामिल हैं। रक्षा, रणनीतिक और दुर्लभ सार्वजनिक उपयोगिता परियोजनाओं को छोड़कर अधिकांश गतिविधियों के लिए ऑफ-लिमिट।	आगे सीआरजेड-1A और सीआरजेड-1B में विभाजित किया गया है। सीआरजेड-1A में पर्यावरण-पर्यटन गतिविधियों की अनुमति देता है। बंदरगाहों और समुद्री लिंक जैसे विशिष्ट बुनियादी ढांचे के लिए सीआरजेड-1B में भूमि पुनर्ग्रहण की अनुमति।
सीआरजेड-II	कवर किए गए क्षेत्र काफी हद तक तट तक या उसके करीब बने हुए हैं। प्रतिबंधित विकास, मुख्य रूप से केवल मौजूदा अधिकृत संरचनाओं की मरम्मत और पुनर्निर्माण की अनुमति देता है।	अधिक उदार, बढ़े हुए फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर), रिसॉर्ट्स के निर्माण और अन्य वाणिज्यिक विकास की अनुमति, शहरीकरण को बढ़ावा देना।
सीआरजेड-III	अपेक्षाकृत अबाधित क्षेत्र, हाई टाइड लाइन (एचटीएल) से 200 मीटर तक फैले नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड) द्वारा संरक्षित। नए निर्माणों, विशेषकर व्यावसायिक निर्माणों पर सख्त नियमन।	घनी आबादी वाले क्षेत्रों में एनडीजेड को घटाकर 50 मीटर कर दिया गया, जिससे तट के करीब अधिक विकास संभव हो सका। कुछ शर्तों के तहत एचटीएल तक रिसॉर्ट्स और होटलों के निर्माण की अनुमति।

सीआरजेड-IV	तटीय जल क्षेत्र और निम्न ज्वार रेखा और 12 समुद्री मील अपतटीय के बीच का क्षेत्र। अपतटीय गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर जोर।	विनियमन इसे जारी रखता है लेकिन कुछ मानदंडों में ढील देता है, जिससे बंदरगाहों और बंदरगाहों जैसे रणनीतिक और बुनियादी ढांचे के उद्देश्यों के लिए भूमि पुनर्ग्रहण और अन्य विकास की अनुमति मिलती है।
पारिस्थितिक संवेदनशीलता	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करने और मानव प्रभाव को कम करने पर उच्च प्राथमिकता।	कड़ी शर्तों के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में भी, पर्यावरण-पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास सहित अधिक मानवीय गतिविधियों की अनुमति देता है।
विकासात्मक फोकस	तट के पास विकासात्मक गतिविधियों को सीमित करने वाले कड़े नियमों के साथ पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देता है।	कुछ पारिस्थितिक विनियमन के साथ, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट विकास को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है।
सार्वजनिक और सामुदायिक प्रभाव	तटीय समुदायों और उनके पर्यावरण को अतिविकास और व्यावसायिक शोषण से बचाने के लिए मजबूत नियम।	पारिस्थितिक और सामुदायिक चिंताओं के साथ आर्थिक लाभ को संतुलित करने का दावा किया गया है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR